संदर्भ सं0 22/7520 2 दिसम्बर 08

सेवा में,
श्री रोहित नन्दन आई0ए0एस0
प्रमुख सचिव,
खाद्व प्रसंस्करण विभाग
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

द्वारा :– निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश।

विषय :– खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की समीक्षा एवं स्थापना की सम्भावनाएँ तलाशने हेतु बैठक विषयक।

महोदय,

आई0आई0ए0 वर्ष 2003 से उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो के उत्थान हेतु कार्य कर रहा है। इस प्रयास में आई0आई0ए0 प्रदेश सरकार को सहयोग देता रहा है और लेता भी रहा है। कुछ अच्छे प्रयास जो प्रारम्भ किये गये थे एवं उनका संक्षिप्त विवरण, वर्तमान स्थिति एवं प्रस्ताव निम्न प्रकार से आपको प्रेशित कर रहे है :–

क्रम सं0	दिनांक	गतिविधि	संक्षिप्त विवरण एवं वर्तमान स्थिति एवं प्रस्ताव
1	जनवरी 2003	आई0आई0ए0 द्वारा प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया गया।	विगत 5 वर्षो से यह कार्यदल सक्रीय रूप से कार्य कर रहा है। उद्यान खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर इस कार्यदल ने अनेक कार्य किये है जिनका विवरण निम्नलिखित गतिविधियों में है। यह कार्यदल आपको आपके प्रयासों में पूर्ण सहयोग करता रहेगा।
2	3 मई 2003	कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो पर सलाहकार समिति का गठन जिसमें आई0आई0ए0 के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वर्किग कमेटी के तीन सदस्य नामित है और अधिशासी निदेशक आई0आई0ए0 को इस समिति का संयोजक बनाया गया है।	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 3 मई 03 को इस सलाहकार समिति का गठन किया गया था। इस सम्बन्ध में जारी अर्द्व .602शा0 पत्र की प्रतिलिपि संलग्नक (क) पर सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित है। लगभग 6 महीनो तक इस सलाहकार समिति की बैठके होती रही। तदोपरान्त प्रदेश सरकार में प्रशासनिक फेरबदल के कारण इस समिति के कार्यकलाप सुचारू रूप से नही चल पाये है। यह एक अच्छा प्रयास था जो जारी रखने से सरकार, औद्योगिक संगठनों एवं विशेषज्ञो के बीच संवाद बना रहेगा जिससे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो को बढ़ावा मिलेगा। आप इस समिति को सक्रीय करना चाहे।

3	23 सितम्बर 2003	उ0प्र0 के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त तथा सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ0प्र0 के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो के लिए एक अलग नीति बनाने का निर्णय लिया गया।	बैठक में निर्णय लिया गया कि आई0आई0ए0 के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कार्यदल के सहयोग से प्रदेश में ''खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति'' बनाई जाए जिसका प्रारूप आई0आई0ए0 द्वारा सरकार को प्रस्तुत किया जाये। आई0आई0ए0 द्वारा एक माह के भीतर ही उ0प्र0 में पहली खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति का प्रारूप 15 अक्टूबर 2003 को सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को सौप दिया। प्रतिलिपि संलग्नक (ख) पर सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित है। अन्ततः प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति घोशित की जा चुकी है। इस नीति में निरन्तर सुधार एवं इसके प्राविधानों को लागू करने की आवश्यकता है क्रम0स0 2 पर वर्णित सलाहकार समिति यदि पुर्नजीवित की जाती है तो यह कार्य सुचारू रूप से हो पाएगा।
4	अक्टूबर 2003	आई0आई0ए0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कार्यदल द्वारा प्रदेश में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग के साथ मिलकर प्रदेश की राजधानी में प्रतिवर्श ''इण्डिया फूड एक्सपो'' का आयोजन करने का निर्णय लिया गया।	फरवरी 2004 में प्रदेश में पहला ''इण्डिया फूड एक्सपो'' सफलतापूर्वक आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश सरकार के अतिरिक्त भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, एपीडा एवं राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का भी सक्रीय योगदान प्राप्त हुआ। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्श इण्डिया फूड एक्सपो का आयोजन आई0आई0ए0 द्वारा किया जाता रहा है और इसका पॉचवा संस्करण फरवरी 2008 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इसके आयोजन में आपका भी सहयोग एवं प्रोत्साहन रहा है। विगत कुछ बर्षो से इस आयोजन के लिये प्रदेश सरकार एवं केन्द्र सरकार से आशातीत सहयोग आई0आई0ए0 को प्राप्त नही हो रहा है। यदि प्रदेश और केन्द्र सरकार का इसमें पूर्ण सहयोग मिलें तो इस गतिविधि से प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो को अवश्य बढ़ावा मिलेगा।
6	21 अक्टूबर 2003	आई0आई0ए0 द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो को प्रदेश में बढ़ावा देने हेतु 12 मण्डलों में उद्यमिता विकास कार्यक्रम की योजना बनाई गई।	उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव तैयार कर प्रदेश सरकार के खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार को भेजा गया। प्रस्ताव पर आई0आई0ए0 को काई उत्तर प्राप्त नही हुआ अतः यह गतिविधि लागू नही की जा सकी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो के लिए एक व्यवहारिक उद्यमिता विकास योजना की आवश्यकता है। आई0आई0ए0 इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर सकता है जिसके लिये आई0आई0ए0 के पास पर्याप्त अनुभव विद्यमान है।

7	नवम्बर 2003	आई0आई0ए0 द्वारा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों के लिये "Project Appraisal & Entrepreneur Assessment- Focus Food Process ing Industry" विशय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन।	यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया एवं प्रतिभागियों ने इस बहुत उपयोगी पाया। इस कार्यक्रम को आई0आई0ए0 द्वारा कराने का मुख्य उद्देश्य यह था कि विभाग के अधिकारियों को उद्योगो की अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं का सीधा अनुभव हो सके और प्रोजेक्ट अपरेजल इत्यादि व्यवहारिक रूप से हो सके।
8	1 जून 06	प्रस्तावित आलू नीति पर कान्सेप्ट पेपर	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रस्तावित आलू नीति पर एक कॉन्सेप्ट पेपर तैयार किया गया जिसे आई0आई0ए0 को आख्या उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया था। आई0आई0ए0 द्वारा इस पर अपना अभिमत 7 अगस्त 2006 को प्रदेश सरकार को उपलब्ध करा दिया गया था।
9	6 जुलाई 06	खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ0प्र0 सरकार के लिए नीति निर्धारण प्रकोष्ठ का गठन	प्रमुख सचिव खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ0प्र0 भासन की अध्यक्षता में इस 15 सदस्यीय प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। जिसमे आई0आई0ए0 भी सदस्य है। इस प्रकोष्ठ ने कुछ समय तो कार्य किया परन्तु हमारी जानकारी के अनुसार अब इसकी गतिविधियॉ नही हो रही है।
10	28 जुलाई 2006	दो दिवसीय राज्य स्तरीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर सेमीनार का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ0प्र0 द्वारा आई0आई0ए0 एवं अन्य औद्योगिक संगठनों के सहयोग से किया गया। यह सेमीनार होटल ताज लखनऊ में आयोजित किया गया था।	इस सेमीनार में आई0आई0ए0 के विभिन्न जिलो से आये 60 उद्यमियों ने भाग लिया तथा आई0आई0ए0 केन्द्रीय कार्यालय द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। इस सेमीनार में कई महत्वपूर्ण फैसले लिये गये तथा इन फैसलों को लागू करने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया जिसमें आई0आई0ए0 भी सदस्य है सेमीनार में लिए गये निर्णयों को पूर्ण रूप से लागू करने से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो को बढ़ावा मिलेगा। एक महत्वपूर्ण निर्णय जो सेमीनार में लिया गया था वह खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो को खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स की अवधि से सम्बन्धित है। निर्णय लिया गया था कि अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार उ0प्र0 सरकार यह लाइसेन्स वर्तमान में एक वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी करेगी। यह निर्णय अभी तक लागू नही हुआ है। मामला राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु में भी रखा गया है। यदि इस प्रकार से लिये गये निर्णय लागू नही होते है तो उद्यमियों का मनोबल टूटता है और इस प्रकार के सेमीनार मे भी सक्रीयता कम होती है। अतः निवेदन है कि इस सेमीनार की प्रोसीडिंग को देखते हुए कुछ एक्शन प्लान तैयार किए जाए।
11	दिसम्बर	आलू आधारित उद्योगो की	इस सेमीनार पर विस्तृत चर्चा 27 दिसम्बर 06 को

	2006	स्थापना पर सेमीनार	प्रमुख सचिव खाद्य प्रसंस्करण विभाग उ0प्र0 सरकार के साथ हुई जिसमें आई0आई0ए0 द्वारा विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये जिसकी प्रतिलिपि संलग्नक (ग) पर प्रेषित है।
12	20 अप्रैल 08	कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में कृषि एवं खाद्व प्रसंस्करण उद्योगों के उत्थान हेतु बैठक	आई0आई0ए0 द्वारा इस बैठक में सक्रियता से भाग लिया गया। कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय ने आई0आई0ए0 से अपेक्षा की कि उन्हे 4–5 ठोस एवं व्यवहारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाये। तद्नुसार आई0आई0ए0 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। पत्र की प्रतिलिपि संलग्नक (घ) पर प्रेषित है। इन प्रस्तावों पर आई0आई0ए0 को कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नही हुआ है।

जनवरी 2007 के बाद आई0आई0ए0 एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के मध्य रोजमर्रा के कामों के अतिरिक्त कोई महत्वपूर्ण गतिविधि नही हुई है। हालॉकि फरवरी 08 में आयोजित ''इण्डिया फूड एक्सपो'' के लिए तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव खाद्य प्रसंस्करण महोदय से तैयारियो/सहयोग पर मिलने के प्रयास किए गये थे परन्तु किसी भी प्रकार का सहयोग प्राप्त नही हुआ।

उपरोक्त रिपोर्ट आपको इस आशय से प्रेषित कर रहे है कि आप प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगो को बढ़ावा देने हेतु उपरोक्त गतिविधियों को जारी रखने के लिये आई0आई0ए0 प्रतिनिधि मण्डल के साथ एक भेट वार्ता करना चाहे।

भेट–वार्ता हेतु समय एवं दिन निर्धारित कर सूचित करने की कृपा करे।

धन्यवाद

भवदीय

डी0एस0 वर्मा
अधिशासी निदेशक

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार